(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी-3229/2018/पन्ना/भू.रा.

श्रीमती सुमन देवी पत्नी रामपाल राजपूत
निवासी ग्राम आमा तहसील शाहनगर
जिला पन्ना हाल निवास ग्राम कुठला
तहसील व जिला कटनी (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1. धुजुआ पुत्र पुनौआ कुम्हार
2. नन्दीलाल पुत्र पुनौआ कुम्हार
दोनों निवासी ग्राम आमा तह. शाहनगर
जिला पन्ना (म.प्र.)
3. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, पन्ना

.... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव द्वारा आज दि. 26.5.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
26-5-18 एडवोकेट
ग्वालियर

ग्वालियर
4.4
1 8
26-5-18

<u>न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.कं. 410 अ-21x 15-16 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका का निम्नानुसार विनय है कि :-

संक्षिप्त तथ्य :-

1- यह कि, ग्राम आमा तहसील शाहनगर में स्थित भूमि ख.नं. 3509/1 एवं 3409/9 रकवा क्रमशः 1.00 है. एवं 1.19 है. कुल किता 2 कुल रकवा 2.19 है. भूमि जो कि अनावेदक कं. 1 व 2 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3229/2018/पन्ना/भू.रा.

सुमन देवी विरूद्ध धुजुआ आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–09–18	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक क्र. 3 शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अजय चर्तुवेदी को ग्राहयता के तर्क पर दिनांक 28.08.18 को सुना गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 410/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ मेरे द्वारा अधीनस्थ अपर आयुक्त सागर का अपील में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.03.2018 एवं निगरानी मेंमो का अवलोकन किया गया । शासकीय पट्टे की भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा WA 539/2017 श्रीमती जया राठी व अन्य विरूद्ध श्री सुम्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2018 निम्नानुसार है– I. The land was granted to the landless person on lease by the State Government. The transfer of land leased to a landless persosn could be affected only after getting approval from the Collector. Since admittedly the approval from the Collector was not sought, such transation	

1/3

(1) (2)

has been rightly found to be void as such transaction is in contravention of statutory provisons"

II. Section 57 of the Code confers ownership in all lands on the state whereas, sub-section (2) contemplantes that if a dispute arises between the State government and any person in respect of any right under sub-section (1) such dispute shall be decided by the State Government or by the Collector. Still further, under section 257 of the Code, the jurisdiction of civil court is barred in respect of any decision regarding any right under sub-section (1) of Section 57 between the State Government and any person. The relevant causes read as under :

" **57 State ownership in all India** – (1) All lands belong to the State Government and it is herby declared that all such lands, including standing and flowing water, mines, qurries, minerals and forests reserved or not, and all right in the sub-soil of any land are the property of the State Government:

Provided that nothing in this section shall, save as otherwise provided in this Code, be deemed of affect any rights of any persons subsisting at the coming into force of this Code in any such property.

(2) Where a dispute arises between the State Government and any person in respect of any right under sub-section (1) such dispute shall be decided by the State Government/Collector

" **257 Exclusive jurisdiction of revenue authorities :-** Except as otherwise provided in this

Code, or in any other enactment for the time being in force, no Civil Court shall entertain any suit instituted or application made to obtain a decision or order on any matter which the State Government, the Board, or any Revenue Officer is by this Code, empowered to determine, decide or dispose of, and in particular and without prejudice to the generality of this provison, no Civil Court shall exercise jurisdiction over any of the following matters:-

(a) any decision regarding any right under sub-section (1) of Section 57 between the State Government and any person.

III. Therefore, the State having granted lease of land to landless persons, had a right over the land in question as owner and the appellants having obtained sale deeds from the landless persons, the matter could be decided only by the State Government or by Collector in terms of Section 57 read with Section 257 of the Code. The sale could not be declared void by the Civil Court as the jurisdiction of the Civil Court is barred in terms of Section 257 read with Section 57 of the Code. In view thereof, We do not find any merit in the present appeal. Accordingly, the same is dismissed.

3/3

4/ अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 में हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण निगरानी अग्राह्य की जाती है। आवेदक अधिवक्ता को नोट कराये।

10.9.18

(आर.के. जैन)
सदस्य

3

4